तथा अन्य विकासपरक सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ जिससे लोगों की कार्य क्षमता बढ़े और उत्पादन व आय में वृद्धि हो सके। और अंतत: देश का उच्चस्तरीय आर्थिक विकास हो सके।

3. पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना
(To increase Capital Formation)

अल्पविकसित देशों में पूंजी का अभाव पाया जाता है। इन देशों में पूंजी की कमी पूंजी-निर्माण व पूंजी संचय में बाधक है। प्रो. रेगनर नर्क्से (R. Nurkse) के अनुसार अल्पविकसित देशों की आय का स्तर निम्न बचत व निवेश के स्तर भी निम्न होते हैं फलत: उत्पादन व आय का स्तर निम्न ही बना रहता है। अत: इस दुश्चक्र को तोड़ने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत होती है। सरकार अपना हस्तक्षेप राजकोषीय नीति के माध्यम से करती है। राजकोषीय नीति के अन्तर्गत करारोपण द्वारा चालू उपभोग को कम करके, सार्वजनिक काम द्वारा श्रम को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आय को बढ़ाकर बचत में वृद्धि करने के प्रयास किये जाते हैं। इससे पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक धन राशि को जुटाना सम्भव होता है। इस तरह राजकोषीय नीति के अन्य उपकरण जैसे सरकार द्वारा नए कर लगाना पुराने करों की दरों में वृद्धि करना, अनुत्पादक व्ययों में कमी लाकर, सार्वजनिक ऋण लेकर, सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरेक प्राप्त कर तथा घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेकर विकास के लिए आवश्यक धन राशि जुटाने का प्रयास करती है। जिसे उत्पादन कार्यों में पूंजी के रूप में निवेश करके अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के उत्पादन व आय को बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक संवृद्धि को तीव्र किया जा सकता है।

4. आय एवं सम्पत्ति की विषमताओं को कम करना
(To Reduce Inequality of Income and Wealth)

विकासशील देशों में आर्थिक विकास में राजकोषीय नीति का

मुख्य उद्देश्य आर्थिक असमानता को दूर करना तथा समाज में आय तथा धन के समान वितरण को स्थापित करना है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत करों की दरों को अधिक प्रगतिशील बनाकर तथा करों में कई तरह की छूटों को देकर समाज में आय व धन के वितरण को समान बनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई आदि क्षेत्रों पर सरकारी व्यय के द्वारा भी निम्न आय-वर्ग के लोगों का रहन सहन सुधारा जा सकता है। निर्धन इसतरह हम यह धारणा स्वीकृत है कि बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक विकास महत्वहीन है।

5. स्फीतिजनक प्रभावों को रोकना (To check the Inflationary Pressures)

अल्पविकसित देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में व्याप्त मुद्रा स्फीति के प्रभावों को कम करना भी होता है। इन देशों में जहाँ बढ़े हुए व्ययों को पूरा करने के घाटे की वित्त व्यवस्था और उसके निहित बढ़ी हुई मुद्रा-पूर्ति के साथ मुद्रा-स्फीति की समस्या जुड़ी हुई है वहाँ कीमत स्थायित्व के लिए राजकोषीय नीति का विशेष महत्व है। बजट प्रक्रिया में समायोजन तथा विभिन्न कर नीतियों के आधार पर आय एवं व्यय में समायोजन के साथ घाटे की वित्त व्यवस्था आदि के रूपों में अतिरिक्त साधनों का इस प्रकार प्रबन्ध होना चाहिए जिससे कि मुद्रा स्फीति तथा उसके हानिकारक प्रभावों को रोका जा सके। यह कार्य सरकार अपनी राजकोषीय नीति को लागू करके कर सकती है। वह अनुत्पादक कार्यों व्ययों को कम करके तथा उपयुक्त कर नीति द्वारा अतिरिक्त साधनों को प्राप्त करके इन देशों के आर्थिक विकास में साधनों की मांग-पूर्ति में सामंजस्य स्थापित कर सकती है।

भारत जैसे विकासशील देश में राजकोषीय नीति के इन प्रमुख उद्देश्यों के अलावा कुछ अन्य

उद्देश्य भी हो सकते हैं जैसे- क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, बचत व निवेश को बढ़ावा देना, विद्यमान संसाधनों को अनुत्पादक क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर मोड़ना आदि। इन उद्देश्यों को पूरा करने में राजकोषीय नीति का कार्यात्मक वित्त का दृष्टिकोण सक्रिय वित्त (Activating finance) के रूप में कार्य करेगा। Activating finance के अनुसार राजकोषीय नीति का ढाँचा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह पूँजी निर्माण के लिए बचतों व संसाधनों को बढ़ाने तथा तीव्र आर्थिक विकास में वृद्धि करे।

Dr Sandhya Rani
Dept of Economics
Maharaja College